

सिंचाई मंत्री (श्री केशर पाण्डेय):

(क) उत्तर प्रदेश के 1980-81 की वार्षिक योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंडक नहर परियोजना पर किए गए खर्च का ब्यौरा निम्नीलिखित है:-

(करोड़ रुपये)

1961 से 1978-79 तक 56.91

1979-80 (प्रत्याशित) 8.85

1980-81 (प्रस्तावित) 9.00

(ख) से (ड). प्रश्न संभवतः रेल पुल के निर्माण से संबंधित है।

रेल मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार गंडक नहर ने अपना मार्ग बदल लिया है जिसके कारण रेल पुल के स्थान के बारे में पुनः जांच करने और नदी नियंत्रण वर्क्स के डिजाइन तैयार करने की आवश्यकता है।

गैस के सिलिण्डरों पर एल्यूमिनियम की सील

1800. श्री तारिक अनवर : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गैस के सिलिण्डरों पर एल्यूमिनियम की सील लगाने की प्रथा बन्द कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली में कुछ अधिकृत विक्रेताओं द्वारा बिना सील के गैस सिलिण्डरों की सप्लाई करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई शिकायतों के प्राप्त होने पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्बरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख). गैस सिलिण्डरों पर एल्यूमिनियम सील लगाना, जो इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा संघ शोषित दिल्ली में प्रारम्भ किया गया था इन सीलों के आवश्यकता अनुसार उपयुक्त न पाये जाने के कारण इनका प्रयोग बन्द किया गया है।

(ग) और (घ). सभी गैस सिलिण्डरों को तरल पेट्रोलियम गैस के बितरणों को सप्लाई किये जाने से पहले इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा सील किये जाते हैं। अगर इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त की जाती हैं तो तेल कम्पनियों द्वारा जांच की जाती है और उनके द्वारा औपचारिक उपाए किये जाते हैं।

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पेट्रोल व डीजल के पम्प

1801. श्री गिरधारी लाल व्यास : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में उन तहसीलों और उप-मंडलीय अधिकारी मुख्यालयों के नाम क्या हैं जहां पेट्रोल और डीजल के पम्प हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कई तहसीलों तथा उपमण्डलीय मुख्यालयों में एक भी पेट्रोल पम्प और डीजल पम्प नहीं है जिसके परिणामस्वरूप लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) सरकार द्वारा इन स्थानों में यथा शीघ्र पम्पों की व्यवस्था करके इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्बरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ख). राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की 11 तहसीलों में से पांच में पेट्रोल/डीजल पम्प स्टेशन हैं। वे भीलवाड़ा मण्डल, शादा, शाहपुर और मण्डलगढ़ हैं। शेष 6 तहसीलों की आवश्यकताएँ इस समय निकट के फुटकर पेट्रोल पम्पों से पूरी की जा रही हैं। इंडियन आयल कारपोरेशन ने पहले ही दो फुटकर पेट्रोल पम्पों की योजना बनाई है जो प्रत्येक असिन्द और जहांजपुर में होंगे और अन्य 4 तहसीलों के लिए मांग की सम्भावनाओं का उद्योग द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

फुटकर पम्पों की स्थापना तेल कम्पनियों द्वारा मांग सम्भावनाओं और कार्य की आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर की जाती है।

गंगा नदी में बाढ़

1802. श्रीमती कृष्णा साहू: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में गंगा नदी की कुल लम्बाई 2,330 किलोमीटर है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 10 लाख वर्ग मीटर का कुल क्षेत्र गंगा नदी में आने वाली बाढ़ से प्रभावित होता है; और

(ग) यदि हां, तो बाढ़ पर नियंत्रण करने और गंगा नदी द्वारा होने वाले भूक्षण को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय): (क) भारत में मुख्य गंगा की कुल लम्बाई 2525 किलोमीटर है।

(ख) गंगा बेसिन में औसतन 43.6 लाख हेक्टेयर भूमि प्रति वर्ष बाढ़ों और जल-निकास अवरोध से प्रभावित होती है।

(ग) चूंकि बाढ़-नियंत्रण राज्य विषय है, इसलिए बाढ़ों पर काबू पाने के उपाय करना और तट-कटाव की रोक-थाम करना संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है। इस कार्य में उनको सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित गंगा बाढ़-नियंत्रण आयोग ने गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक योजना की रूपरेखा की है और राज्यों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर घाघरा, गोमती, अधवाड़ा तथा गहानन्दा नदियों के उप-बेसिनों के लिए व्यापक योजनाएं तैयार की हैं। राज्यों द्वारा संबंधित आंकड़े एकत्र करने के बाद गंगा बेसिन की अन्य नदियों के लिए उप-बेसिन योजनाओं को भी तैयार करने का प्रस्ताव है। गंगा बेसिन में बाढ़ों पर काबू पाने का कार्य सीमित है क्योंकि कुछ बृहद सहायक नदियों पर जल-संचयन जलाशयों के स्थल नेपाल क्षेत्र में पड़ते हैं और ये निर्माण-कार्य नेपाल सरकार की स्वीकृति तथा सहयोग से ही शुरू किए जा

सकते हैं जिसके लिये अनुरोध किया गया है। इस बीच राज्य सरकार कमजोर स्थलों पर बाढ़-सुरक्षा तटबंध, नदी नियंत्रण वर्क्स और कटाव-रोधी निर्माण-कार्य कर रही है।

Supply of Diesel and Kerosene to West Bengal

1803. SHRI PIUS TIRKEY: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether any request has been received by the Central Government from the West Bengal Government during the last six months for allocation of more diesel and kerosene; and

(b) if so, the steps taken by Government in this matter?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) Yes, Sir.

(b) The monthly allocations of high speed diesel (HSD) oil and kerosene to West Bengal have been made after taking into account the overall availability of these products, historical sales and movement capacity. Additional allocations of diesel and kerosene were also made for West Bengal over and above their original allocations in response to the requests of the State Government in the last few months.

Power cut in Calcutta

1804. SHRI PIUS TIRKEY: Will the Minister of ENERGY AND COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a drastic cut of power in Calcutta at present; and

(b) the steps Government propose to take to meet the supply of power in Calcutta?